वर्ष 1 · अंक **11**
जयपुर, रविवार, 25 अक्टूबर 2026
सप्ताह 19–25 अक्टूबर 2026

The Consulting Crew
GST · इनकम टैक्स · ROC · पेरोल · सलाह
क्लाइंट्स और दोस्तों के लिए मुफ़्त

THE CONSULTING CREW

आज के समाचार

BUSINESS WEEKLY

हर खबर जो आपके बिज़नेस के काम आए

10 साल की G-sec	रेपो रेट	ब्रेंट	निफ्टी 50	रुपया	अगली तारीख़
7.474%	5.50%	$116.72	22,600.00	94.94/$	31 Oct
▲ 6 अक्तूबर से +28 bps	7 अक्तूबर से वही	▲ 2 अक्तूबर के $102.70 से	▼ −2.4%, उछाल वापस गई	▲ अक्तूबर में +0.93%	तीन चीज़ें, एक नहीं

इस अंक में

1 कर्ज़ 2 टैक्स 3 GST 4 कर्ज़ 5 लागत 6 व्यापार 7 राजस्थान 8 संदर्भ + ज़रूरी तारीख़ें

बड़ी खबर · कर्ज़

RBI ने 25 अंक बढ़ाए। बाज़ार 28 और जोड़ चुका है

सत्रह दिन, कोई ऐलान नहीं, और लगातार दसवाँ हफ़्ता यील्ड चढ़ने का — सरकारी बॉन्ड के लिए तीस साल का सबसे बुरा दौर। यह आपके कर्ज़ तक पहुँचा या नहीं, यह इस पर है कि वह किस benchmark पर बैठा है।

10 साल की G-sec 6 अक्तूबर को 7.193% · 23 अक्तूबर को 7.474%

ऐलान छोटा हिस्सा था, और चुपचाप वाला हिस्सा बड़ा है। **7 अक्तूबर** को MPC ने रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% की, और इस अख़बार ने उसे दर के फ़ैसले की तरह छापा। उसके बाद से **10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड** 6 अक्तूबर के **7.193%** से बढ़कर **23 अक्तूबर** को **7.474%** हो गई — सत्रह दिन में करीब **28 आधार अंक**, और किसी ने कोई फ़ैसला नहीं लिया। यह लगातार **दसवाँ हफ़्ता** था यील्ड चढ़ने का, और Business Standard के हिसाब से सरकारी बॉन्ड के लिए **तीन दशक** का सबसे बुरा दौर।

दो benchmark, दो रफ़्तार — और ज़्यादातर कर्ज़दारों को पता ही नहीं कि वे किस पर हैं। **external benchmark (EBLR)** वाला कर्ज़ रेपो से जुड़ा है: उसने 25 अंक ले लिए और अगली MPC तक और कुछ नहीं लेगा। **MCLR** वाला कर्ज़ बैंक की अपनी लागत से जुड़ा है, जो बॉन्ड बाज़ार और जमा बाज़ार मिलकर तय करते हैं — यानी वह ये 28 अंक भी ले रहा है, अपने reset चक्र पर, और चेताने के लिए कोई ऐलान नहीं होगा। मोटे तौर पर, retail और सूक्ष्म व छोटे उद्यमों के floating कर्ज़ जो external benchmark के नियम के बाद मंज़ूर हुए, वे EBLR पर हैं; मझोले उद्यमों का और पुराना बहुत सारा कर्ज़ आज भी MCLR पर है। आपका sanction letter बताता है कि कौन सा।

क्यों हो रहा है, यह रहस्य नहीं है और ख़त्म भी नहीं हुआ है। जो वजहें गिनाई जा रही हैं: **कच्चा तेल** — 23 अक्तूबर को ब्रेंट करीब **$116.72** पर बंद हुआ — दुनिया भर में ऊँची यील्ड, बैंकिंग में तंग पड़ी नक़दी, और यह उम्मीद कि RBI अभी रुका नहीं है; कुछ अर्थशास्त्री अब **दिसंबर** में बड़े क़दम की बात कर रहे हैं। **SBI Research** 10 साल की यील्ड यहाँ से **7.6%** देखता है; Trading Economics तिमाही के अंत तक नरम 7.32% का मॉडल बनाता है — और एक बैंक के अपने शोध और एक डेटा कंपनी के बीच का यह फ़र्क़ दोनों आँकड़ों से ज़्यादा काम का है: भरोसेमंद कोई नहीं मानता कि इस तिमाही यह नीचे जा रही है।

आपको क्या करना है

इस हफ़्ते sanction letter निकालिए और वह शब्द ढूँढ़िए — **EBLR** या **MCLR** — और उसके साथ **reset की तारीख़**। अगर MCLR लिखा है, तो आपकी दर उस बाज़ार के साथ चल रही है जिसका ऐलान आपको कोई नहीं करेगा, और पिछले सत्रह दिन उसमें पहले से शामिल हैं — EMI बदली हो या न बदली हो। फिर अपने relationship manager से एक सवाल लिखकर पूछिए: अगले reset पर नई दर और नई अवधि क्या होगी। अभी दर क्या है — यह नहीं; क्या होगी — यह। जो बैंक EMI वही रखकर चुपचाप अवधि बढ़ा देता है, उसने आपको बताया कुछ नहीं और वसूला बहुत कुछ है।

ज़रूरी तारीख़ें

अक्तूबर – नवंबर 2026

28 अक्टू — 3 दिन बाकी

Jio Platforms की listing
deadline नहीं। ₹30,213 करोड़ — रुपये के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा इश्यू

31 अक्टू — 6 दिन बाकी

तीन चीज़ें, एक नहीं
Q2 का TDS statement · जहाँ s.92E लागू है वहाँ Form 3CEB · ₹1 लाख से ऊपर self-assessment tax। शनिवार है — पैसा 30 को चलाइए

1 नव — 7 दिन बाकी

deadline नहीं
इस तारीख़ से लिया credit input-services refund के लिए पात्र — जब Act में संशोधन हो जाए

7 नव — 13 दिन बाकी

TDS जमा
अक्तूबर का

8 नव — 14 दिन बाकी

दिवाली · मुहूर्त कारोबार
रविवार का सत्र, दोपहर 2:20–3:30, उनहत्तर साल में पहली बार दोपहर को। संवत 2083

11 नव — 17 दिन बाकी

GSTR-1
अक्तूबर, मासिक भरने वाले

15 नव — 21 दिन बाकी

TDS certificates — Q2
deductees को Form 16A

16 नव — 22 दिन बाकी

अक्तूबर का WPI
पहला सरकारी लागत आँकड़ा जिसमें इस महीने का कच्चा तेल होगा

20 नव — 26 दिन बाकी

GSTR-3B
अक्तूबर, मासिक भरने वाले

21 नव — 27 दिन बाकी

ITR — ऑडिट वाले
31 अक्तूबर से बढ़ी। self-assessment tax ₹1 लाख पार करे तो 31 अक्तूबर तक भर दीजिए

टैक्स · 31 अक्तूबर

ऑडिट की तारीख़ टिकी। अब शनिवार को तीन अलग चीज़ें गिर रही हैं

Q2 का TDS statement · Form 3CEB · self-assessment tax · सभी 31 अक्तूबर

आगे कुछ नहीं आया, और और सबसे पहले यही दर्ज करने लायक़ है। इस अख़बार के पिछले अंक की बड़ी ख़बर यही थी कि **21 अक्तूबर** ही तारीख़ है और तीसरी नहीं आएगी। 21 निकल गई, कोई नया circular अधिसूचित नहीं हुआ, और जिन्होंने extension को लंबी राहत की पहली क़िस्त माना वे ग़लत थे। तारीख़ टिक गई। इससे आपको छह दिन मिले हैं, क्योंकि **31 अक्तूबर** पर अब तीन ज़िम्मेदारियाँ हैं जिन्हें आम तौर पर एक ही मानकर निपटाया जाता है।

एक: जुलाई से सितम्बर का **Q2 TDS statement**। दो: जहाँ समूह में कहीं भी section **92E** लागू है वहाँ **Form 3CEB** — वह तारीख़ ऑडिट वाले extension के साथ कभी खिसकी ही नहीं और अब भी नहीं खिसकती; उसकी return **30 नवंबर** है। तीन, और यही वह है जो किसी की सूची में नहीं होती क्योंकि यह filing नहीं है: अगर आपका **self-assessment tax ₹1 लाख** पार करेगा, तो 31 तक भर दीजिए। ऑडिट वालों की return 21 नवंबर है, मगर पिछले extensions में CBDT ने उस हद से ऊपर **section 234A** का ब्याज मूल तारीख़ से चलने दिया है, और इस बार किसी आदेश ने उलटा नहीं कहा।

31 तारीख़ सबसे ज़्यादा आधी-अधूरी क्यों रहती है, इसकी वजह लापरवाही नहीं, ढाँचा है: तीनों काम तीन अलग लोगों से होते हैं। TDS statement के लिए वह चाहिए जो payroll और vendor भुगतान देखता है। Form 3CEB के लिए वह accountant चाहिए जिसने transfer pricing की study पर दस्तख़त किए — ज़्यादातर समूहों में वह वही फ़र्म नहीं होती जिसने ऑडिट किया। self-assessment के भुगतान के लिए वह चाहिए जो इतनी बड़ी रक़म मंज़ूर कर सके, और उसे आम तौर पर तब तक बताया ही नहीं जाता जब तक हिसाब आख़िरी न हो जाए। शनिवार बैंकों और portal के लिए कामकाजी दिन है; उन तीसरे व्यक्ति के लिए अक्सर नहीं होता।

> **आपको क्या करना है**
>
> आज एक संदेश भेजिए जिसमें तीनों काम और हर एक का ज़िम्मेदार नाम से लिखा हो, और गुरुवार तक हर एक के सामने हाँ माँगिए। 31 का शनिवार होना ही वह बात है जो हर साल गड़बड़ करती है: अगर self-assessment के भुगतान के लिए ऐसा signatory चाहिए जो हफ़्ते के आख़िर में मेज़ पर नहीं होता, तो पैसा **शुक्रवार 30** को ही चलना होगा — यानी छह नहीं, पाँच कामकाजी दिन।

30 नव — 36 दिन बाकी
ITR — transfer pricing
s.92E वाले मामले

4 दिस — 40 दिन बाकी
MPC का फ़ैसला
बैठक 2–4 दिसंबर। कुछ अर्थशास्त्री बड़े क़दम की उम्मीद कर रहे हैं

ये आम तारीख़ें हैं। सरकार आगे बढ़ाए तो अगले अंक में बता देंगे। टर्नओवर और राज्य के हिसाब से फ़र्क़ पड़ता है — भरोसा करने से पहले एक बार पूछ लीजिए।

सारी तारीख़ें कैलेंडर में डालें

TCC की सलाह

इस हफ़्ते ये तीन काम कर लीजिए

1. **sanction letter में वह शब्द ढूँढ़िए। EBLR** या **MCLR**, और उसके साथ **reset की तारीख़**। MCLR लिखा हो तो आपकी दर उस बॉन्ड बाज़ार के पीछे चल रही है जो सत्रह दिन में बिना ऐलान 28 आधार अंक हिल चुका है। फिर rate reset history और नई अवधि लिखकर माँगिए।

2. **31 अक्तूबर को शुक्रवार से पीछे की ओर चलाइए।** तीन ज़िम्मेदारियाँ, तीन अलग लोग: **Q2 का TDS statement**, जहाँ s.92E लागू है वहाँ **Form 3CEB**, और ₹1 लाख पार करे तो **self-assessment tax**। 31 शनिवार है, इसलिए भुगतान असल में 30 को ही चलना चाहिए।

3. **पूरी sheet नहीं, भाड़े की लाइन ठीक कीजिए।** ब्रेंट तीन हफ़्ते में $102.70 से $116.72 हो गया और **16 नवंबर** तक किसी सरकारी लागत आँकड़े में यह है ही नहीं। इस हफ़्ते सबसे तेज़ चलने वाली लाइन ठीक कीजिए और सोमवार से हर quotation में ईंधन का clause डालिए।

GST · सत्रह दिन बाद

काउंसिल बैठ चुकी, FAQ आ चुके, और एक भी नियम नहीं बदला

57वीं काउंसिल 8 अक्तूबर · CBIC के FAQ 9 अक्तूबर · अधिसूचनाएँ: एक भी नहीं

सिफ़ारिश नियम नहीं होती, और सत्रह दिन इतने होते हैं कि दिख जाए इसकी क़ीमत क्या है। **8 अक्तूबर** को काउंसिल के बैठने के बाद CBIC ने 9 अक्तूबर को **FAQ** जारी किए और उसके चेयरमैन ने 15 को सार्वजनिक रूप से सुचारु अमल पर ज़ोर दिया। दोनों काम के हैं। दोनों में से कोई अधिसूचना नहीं है, और उस दिन जो सिफ़ारिश हुई — गिरफ़्तारी का अधिकार हटाना, मुक़दमे की सीमा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़, सामान्य जुर्माना ₹25,000 से ₹10,000, कर्मचारियों के बीमा पर credit की वापसी — उनमें से कुछ भी आज क़ानून नहीं है।

CBIC के अपने FAQ यह सबसे साफ़ शब्दों में कहते हैं: ज़्यादातर बातें सिफ़ारिशें हैं या CGST Act, CGST Rules, IGST Act और दर-अधिसूचनाओं में *प्रस्तावित* संशोधन। और एक बड़ी बात के साथ ऐसी तारीख़ लगी है जिसे दो बार पढ़ना चाहिए — returns में liability और ITC के mismatch सुधारने की वैकल्पिक व्यवस्था **अप्रैल 2027** की return अवधि से प्रस्तावित है। यानी अठारह महीने दूर। अक्तूबर 2026 में इसे राहत की तरह छापा गया।

असल नुक़सान यह नहीं है कि राहत देर से आएगी। नुक़सान यह है कि जिस कारोबार को अक्तूबर में बता दिया गया कि गिरफ़्तारी का अधिकार हट गया और कर्मचारियों के बीमा पर credit लौट आया, वह उस पर अमल करेगा — credit ले लेगा, समन का जवाब बदल देगा — ऐसे नियम पर जो है ही नहीं, और बीच के अंतर का ब्याज और जुर्माना भरेगा। दो बातें देखने लायक़ हैं क्योंकि वे असल के ज़्यादा क़रीब हैं: छोटे e-commerce विक्रेताओं के लिए आसान registration, और पात्र छोटे B2C करदाताओं के लिए सैद्धांतिक रूप से वैकल्पिक **सालाना return के साथ तिमाही भुगतान**। सैद्धांतिक रूप से का मतलब लागू नहीं है।

कर्ज़ · नक़दी

22 अक्तूबर को बैंकिंग सिस्टम के पास ₹541 करोड़ बचे थे। यह कुछ भी नहीं है

RBI ने एक हफ़्ते में तीन VRR नीलामियों से ₹2 लाख करोड़ डाले

आँकड़े को अनुपात में रखिए, और तो वह आँकड़ा लगना ही बंद हो जाता है। **22 अक्तूबर** को बैंकिंग सिस्टम में बची नक़दी **₹541.95 करोड़** रह गई — जिस सिस्टम में रोज़ लाखों करोड़ चलते हैं, वहाँ यह गद्दी नहीं, हिसाब की गोलाई है। RBI ने उसी हफ़्ते तीन variable rate repo नीलामियों से कुल **₹2 लाख करोड़** डाले, और SBI Research **19 अक्तूबर** से repo नीलामियों के ज़रिये **₹2.5 ट्रिलियन** गिनता है। जो वजहें बताई गईं वे आम और मौसमी हैं: advance tax वग़ैरह का बाहर जाना, और त्योहारी नक़दी की माँग।

SBI Research ने इस जोड़ को मिला-जुला संकेत कहा और बात सही है: बैंक अपना रुख calibrated tightening पर ले आया है और साथ ही ढाई ट्रिलियन रुपये सिस्टम में डाल रहा है। दोनों एक साथ सच हैं क्योंकि वे अलग-अलग समस्याओं के जवाब हैं — रुख तिमाहियों की महँगाई का मामला है, नक़दी डालना दिनों के निपटान का। साथ-साथ वह रुपये को भी सँभाल रहा है: 16 अक्तूबर तक के हफ़्ते में भंडार **$5.01 अरब** घटकर **$721.02 अरब**, और तेल कंपनियों के लिए सरकारी बैंक उसकी ओर से डॉलर ख़रीद रहे हैं।

तंग सिस्टम छोटे कर्ज़दार के साथ जो करता है वह दर नहीं है। वह क़तार है। renewal में ज़्यादा वक़्त लगता है, मंज़ूर मगर बिना निकाली limits दोबारा देखी जाती हैं, और जो बैंक अगस्त में आपकी drawing power पर ढीला था वह नवंबर में stock statement समय पर माँगता है। इनमें से कुछ भी चिट्ठी बनकर नहीं आता; आता है उस फ़ोन की शक्ल में जिसका जवाब चार दिन नहीं मिलता। त्योहारी पखवाड़ा इसे जानने का सबसे ख़राब वक़्त है — और ज़्यादातर कारोबार उसी वक़्त जानते हैं।

आपको क्या करना है

दावा बिलकुल वैसे ही करते रहिए जैसे सितम्बर में कर रहे थे। अगर आपके accountant या software ने काउंसिल की सिफ़ारिश के भरोसे **कर्मचारियों के health और life insurance** पर credit खोल दिया है, तो उसे नोटिस आने पर नहीं, अभी पलट दीजिए — section 17(5) में संशोधन नहीं हुआ है और वह credit उपलब्ध नहीं है। आज इस पर करने लायक़ एक ही काम है, डायरी में लिखना: हर महीने के पहले कामकाजी दिन CBIC का notifications पन्ना देखिए, और FAQ को वही मानिए जो वह है — एक प्रस्ताव की व्याख्या।

आपको क्या करना है

अगर आपका **CC/OD renewal** अब से जनवरी के बीच देय है, तो उसे आख़िरी पखवाड़े में नहीं, इसी हफ़्ते शुरू कीजिए। अगले तीन महीने stock और debtor statements बिना तक़ाज़े के देय तारीख़ पर दीजिए, क्योंकि तंग तिमाही में वही फ़ाइल चलती है जो पूरी होती है। और अगर आपके पास मंज़ूर limit है जो आपने निकाली नहीं और नए साल में ज़रूरत पड़ सकती है, तो शाखा से अभी बात कीजिए — जब तक वह बिना इस्तेमाल की limit है, उस line item से पहले जिसे किसी को दोबारा देखने को कहा गया है।

व्यापार · रुपया

इस हफ़्ते tariff का पाँचवाँ आँकड़ा आया। रुपया भी उल्टी तरफ़ गया

23 अक्तूबर को रुपया 94.94, महीने में 0.93% मज़बूत · भंडार -$5.01 अरब

पिछले अंक ने tariff की कोई दर नहीं छापी, और और इस हफ़्ते ने उसे बचाव नहीं, एहतियात बना दिया। चार बचाव-योग्य आँकड़े पहले से चल रहे थे — फ़रवरी के framework में 25% और फिर **18%**, अमेरिकी Supreme Court का reciprocal tariffs को गिराना, और कुछ उत्पादों पर executive order से **10%**। अब पाँचवाँ आ गया है: एक रिपोर्ट उसी फ़ैसले के बाद **Section 122** के तहत सार्वभौमिक **15%** duty की बात करती है। यह एक ही स्रोत से है और यह अख़बार इसे तय नहीं मान रहा — मगर आठ महीने में पाँचवाँ आँकड़ा अपने आप में नतीजा है, और यही वजह है कि इनमें से कोई भी contract में न डालें।

ख़ुद समझौते पर हफ़्ते ने शब्द हिलाए, काग़ज़ नहीं। **मार्को रुबियो** ने 19 अक्तूबर को कहा कि लगभग **99%** काम हो चुका है और अंतिम रूप महीनों नहीं, हफ़्तों की बात है; **डोनाल्ड ट्रंप** ने 20 को कहा कि यह "काफ़ी क़रीब" है। इसके उलट **निर्मला सीतारमण** ने 5 अक्तूबर को कहा था कि बातचीत एक पठार पर पहुँच गई है और आगे रियायतें मुश्किल होंगी, और **24 अक्तूबर** के एक AP विश्लेषण को सार्वजनिक रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिला जो साबित करे कि संधि पर दस्तख़त हुए या हर मुद्दा सुलझ गया। निन्यानबे प्रतिशत हो गया — यह आसान निन्यानबे का ब्योरा है।

इस बीच मुद्रा निर्यातकों के ख़िलाफ़ चली — और यही हिस्सा कोई ख़बर नहीं बनाता, क्योंकि देखने में अच्छी ख़बर लगता है। 23 अक्तूबर को रुपया **94.94** पर बंद हुआ, हफ़्ते भर में लगभग सपाट मगर अक्तूबर में **0.93% मज़बूत**। मज़बूत रुपया हर डॉलर बिल पर आपकी वसूली घटाता है, और उसी वक़्त कच्चा तेल आपकी लागत बढ़ा रहा है — एक ही तिमाही में दोनों तरफ़ से दबाव। यह संयोग नहीं है: RBI मुद्रा सँभाल रहा है — 16 अक्तूबर तक के हफ़्ते में भंडार **$5.01 अरब** घटकर **$721.02 अरब**, 10 तारीख़ को सरकारी तेल कंपनियों के लिए विशेष डॉलर खिड़की, और उसकी ओर से डॉलर ख़रीदते सरकारी बैंक।

लागत · कच्चा तेल

ब्रेंट $116 पर है। आप जो लागत के आँकड़े बोल रहे हैं वे $102 पर लिए गए थे

2 अक्तूबर को $102.70 · 23 अक्तूबर को $116.72 · अगला WPI 16 नवंबर

तीन हफ़्ते, और और पूरी costing sheet पुरानी पड़ चुकी है। इस अख़बार ने 2 अक्तूबर को ब्रेंट **$102.70** पर छापा था। **23 अक्तूबर** को वह करीब **$116.72** पर बंद हुआ — **एक ही दिन में लगभग 3.1% ऊपर** — और इस अंक के जाते वक़्त भी $117 के आसपास था। यानी **तीन हफ़्ते में क़रीब 14%**, उस एक input पर जो लगभग हर दूसरे input के भीतर बैठा है: भाड़ा, packaging की फ़िल्म, resin, रंग, वह बिजली जो ग्रिड से नहीं आती, और हर डिलीवरी की डीज़ल वाली लाइन।

अब इसे उस आँकड़े के साथ रखिए जो हर कोई बोल रहा है। सितम्बर की थोक महँगाई **11.39%** आई, जिसमें **ईंधन और बिजली 25.85%** — और इसी अख़बार ने हफ़्ता भर पहले इस पर काफ़ी ज़ोर दिया था, सही ही। मगर वह आँकड़ा **सितम्बर** नापता है। वह तब लिया गया जब ब्रेंट $102 के पास था। इस महीने जो हुआ वह उसमें है ही नहीं और **16 नवंबर** को अक्तूबर का WPI आने तक किसी सरकारी आँकड़े में नहीं होगा। सार्वजनिक रूप से चल रहा सबसे ताज़ा लागत आँकड़ा उस बाज़ार से पाँच हफ़्ते पीछे है जिसे वह बताने के लिए है।

इसीलिए इस पखवाड़े की हिदायत सब्र के उलट है। जो कारोबार नवंबर का आँकड़ा आने तक दाम नहीं बदलेगा, वह नवंबर और दिसंबर का काम सितम्बर की लागत पर quote करेगा, और जनवरी में पता चलेगा। उल्टा तर्क — कि कच्चा तेल चंचल है और वापस गिर सकता है — सही है, और इसीलिए जवाब आँकड़ा नहीं, **clause** है: ऑर्डर आज की लागत पर लगाइए और लिखकर कहिए कि ईंधन से जुड़ा हिस्सा तय प्रतिशत से ज़्यादा किसी भी तरफ़ हिले तो क्या होगा। यह ग्राहक की भी उतनी ही हिफ़ाज़त करता है जितनी आपकी — और इसीलिए इसे माँगा जा सकता है।

10 अक्तूबर के उसी पैकेज का एक और बदलाव जानने लायक़ है: बिना underlying exposure के hedge करने की सीमा घटाकर **$5 मिलियन** के बराबर कर दी गई।

आपको क्या करना है

यह मानना छोड़िए कि गिरता रुपया पतले quotation को ढँक लेगा। क़रीब दो साल तक ढँकता रहा, और इस महीने उसने उल्टा किया — जब आपकी लागत बढ़ रही थी। यानी जो quotation सिर्फ़ 96 पर चलता है वह चलता ही नहीं। दाम उस दिन की दर पर लगाइए और राय नहीं, **वसूली को hedge** कीजिए: पक्के निर्यात ऑर्डर पर forward सस्ती निश्चितता है, और 10 अक्तूबर के नियम ऐसी ही cover को खुलकर देते भी हैं, क्योंकि उसके पीछे underlying है। tariff को दाम से बाहर रखिए और **price-revision clause** में डालिए, शिपमेंट की तारीख़ पर लागू duty से जुड़ा हुआ — यह हिदायत अब तीन अंक पुरानी है और पाँच अलग आँकड़ों से ज़्यादा जी चुकी है।

बाज़ार

23 अक्तूबर 2026 तक का हफ़्ता · पाँच कारोबारी दिन

सूचकांक	बंद भाव	हफ़्ता
Nifty 50	22,600.00	-2.4%
Sensex	73,123.83	-2.2%

पिछले पखवाड़े की सुधार का ज़्यादातर हिस्सा चला गया। निफ्टी शुक्रवार को **22,600.00** पर बंद हुआ, 23,146.15 से हफ़्ते भर में क़रीब **2.4%** नीचे, और सेंसेक्स **73,123.83** पर, क़रीब **2.2%** नीचे। **बैंक निफ्टी 2.8% गिरा**, और यही काम की लाइन है: जिस हफ़्ते 10 साल की यील्ड चढ़ी और सिस्टम की नक़दी लगभग शून्य हो गई, उसी हफ़्ते बैंकों की अगुवाई में गिरावट — यानी पहले पन्ने की कर्ज़ वाली कहानी क़र्ज़ देने वालों के भाव में दिख रही है। $116 के ऊपर कच्चा तेल और वैश्विक अनिश्चितता बाक़ी वजहें बताई गईं। इसी अख़बार ने पिछले दो हफ़्तों को सिलसिला टूटने की तरह छापा था; पखवाड़ा मोड़ नहीं होता, और साथ वाला लेखा-जोखा इसे चुपचाप छोड़ने के बजाय हमारे ख़िलाफ़ दर्ज करता है।

आपको क्या करना है

पिछले महीने के अपने तीन सबसे बड़े purchase order खोलिए और **भाड़े की लाइन** देखिए। अगर वह अक्तूबर के मध्य से पहले लगी थी तो वह अभी से ग़लत है, और वही आपकी सबसे तेज़ चलने वाली लाइन है। पहले उसी को ठीक कीजिए, पूरी sheet को नहीं — इस हफ़्ते एक सही लाइन अगले महीने की पूरी revision से बेहतर है। फिर सोमवार से भेजे जाने वाले हर quotation में **ईंधन का clause** जोड़िए: एक वाक्य, कि दाम quotation की तारीख़ की ईंधन लागत मानकर है और तय दायरे से बाहर हिलने पर फिर खुलेगा। कच्चे तेल का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उसके ख़िलाफ़ तय दाम पर दस्तख़त करना बंद कर सकते हैं।

राजस्थान · RIICO

240 भूखंडों के लिए 449 आवेदन। RIICO में इससे अच्छे आसार कहीं नहीं

Direct Allotment Scheme · बारहवाँ चरण · ग्यारह चरणों में 1,986 भूखंड

पिछले अंक ने इसके बारे में पूछने को कहा था, और और यह रहा वह जवाब, आँकड़ों के साथ। RIICO की **Direct Allotment Scheme** के बारहवें चरण में **240 भूखंडों के लिए 449 आवेदन** आए — हर भूखंड पर दो से कुछ कम आवेदक। इसे e-auction के सामने रखिए, जहाँ एक अच्छा भूखंड दर्जनों बोलीदार खींच लेता है: उदयपुर के माल की तूस में दो भूखंडों पर कुल क़रीब **68** उद्यमी आए। direct allotment बेहतर तमीज़ वाली लॉटरी नहीं है; यह अलग क़तार है, और कहीं छोटी।

और पैमाना छोटा भी नहीं है — इसी बात पर ज़्यादातर लोग इस रास्ते को ग़लत समझते हैं। पहले ग्यारह चरणों में इस योजना ने **1,986 औद्योगिक भूखंड** दिए हैं, जिनके बदले RIICO **₹19,700 करोड़** से ज़्यादा का प्रस्तावित निवेश गिनता है — यानी हर भूखंड पर क़रीब ₹9.9 करोड़ का वादा, जिससे पता चलता है कि योजना में असल में किस आकार की यूनिट बैठी है। और कुल आवंटन तेज़ी से बढ़ा है: इस वित्त वर्ष की अप्रैल–जून तिमाही में **1,038 भूखंड**, पिछले साल की उसी तिमाही के **214** के मुक़ाबले — लगभग पाँच गुना, और FY 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खुले, जिनमें जयपुर का **हुक्कन** भी है।

एक चेतावनी इसी ख़बर में बनती है, क्योंकि वह उसी निगम से उसी साल की है। RIICO ने अकेले **1 अप्रैल से 15 जून** के बीच आवंटित ज़मीन के बक़ाया में **₹100 करोड़** से ज़्यादा वसूले। जो संस्था पाँच गुना भूखंड दे रही हो और साथ-साथ बक़ाया इतनी सख़्ती से वसूल रही हो, वह आपको बता रही है कि आपके आवंटन की चूकी हुई क़िस्त के साथ वह क्या करेगी। allotment letter का भुगतान कार्यक्रम project plan से पहले पढ़िए, बाद में नहीं।

आपको क्या करना है

दो काम, और पहले की कोई deadline नहीं है — इसीलिए वह होता ही नहीं। जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से लिखकर पूछिए कि आपकी यूनिट और project **Direct Allotment Scheme** में पात्र हैं या नहीं, और अगले दौर का चरण नंबर तथा आवेदन की खिड़की माँगिए — चरण नंबर डायरी में लिखा जा सकता है, "जल्दी" नहीं। दूसरा, ज़मीन चाहने से पहले: यह योजना प्रति भूखंड क़रीब ₹9.9 करोड़ के वादे के हिसाब से बनी है, इसलिए अगर आपका project उससे काफ़ी छोटा है तो पूछिए कि कौन सी श्रेणी या कौन सा छोटा औद्योगिक क्षेत्र आप पर बैठता है — ग़लत क़तार में आवेदन देकर एक चरण गँवाने से बेहतर है।

स्टार्टअप की खबरें

19 – 23 अक्तूबर 2026

- शांत हफ़्ता: **17 स्टार्टअप** ने **$184 मिलियन** से ज़्यादा जुटाए, हर हिसाब से पिछले हफ़्ते से कम। **Even Health** ने Khosla Ventures की अगुवाई में Series B में **$50 मिलियन** लिए — एक ही चेक में पूरे हफ़्ते का चौथाई से ज़्यादा।
- जयपुर के पाठक के लिए ध्यान देने लायक़: **The Pant Project** ने Mirae Asset Venture Investments की अगुवाई में Series B में **$11.5 मिलियन** जुटाए — made-to-measure कपड़े, और महीनों बाद पहली बार इतनी रक़म उस श्रेणी में गई है जिसमें इस अख़बार के ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पाठक असल में बैठते हैं। **AuxoAI** ने $20.7 मिलियन और **Firstwork** ने Earlybird की अगुवाई में Series A में $15 मिलियन लिए।
- हफ़्ते का असली पैसा venture था ही नहीं। **Jio Platforms** का **₹30,213 करोड़** का IPO 23 को बंद हुआ — रुपये के हिसाब से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इश्यू, भारी oversubscription के साथ, listing **28** को। इस वाक्य के दो आँकड़े विवादित हैं: एक ब्रोकर आकार ₹30,187.6 करोड़ बताता है, और subscription अलग-अलग cut-off पर 22.19 और 20.58 गुना दोनों छपा है। परिमाण पर कोई शक नहीं है।

संदर्भ · आने वाले हफ़्ते

शनिवार तीन लाता है। फिर नवंबर आता है, एक ऐसे रविवार के साथ जिस दिन बाज़ार चलेगा

25 अक्तूबर से 30 नवंबर 2026

उनमें से पहली तक छह दिन, और और बाक़ी कैलेंडर असामान्य रूप से आसानी से ग़लत पढ़ा जाता है। **31 अक्तूबर** तीन अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो साथ वाले कॉलम में दी हैं। **1 नवंबर** deadline है ही नहीं — यह वह तारीख़ है जिससे लिया गया credit 57वीं काउंसिल की सिफ़ारिश वाले input-services refund के लिए पात्र होगा, जब Act में संशोधन हो जाए; यानी देखने की चीज़, भरोसे की नहीं। फिर **7 नवंबर** अक्तूबर का TDS भुगतान, और महीने की असली filing दौड़ शुरू: **11 नवंबर** GSTR-1, **15 नवंबर** Q2 के TDS certificates Form 16A में, **20 नवंबर** GSTR-3B।

8 नवंबर दिवाली है, और इस बार साथ में वह चीज़ है जो बाज़ारों ने उनहत्तर साल में नहीं की। एक्सचेंजों ने रविवार 8 नवंबर का **मुहूर्त कारोबार दोपहर** के सत्र में रखा है — pre-open दोपहर 2:05 से, बाज़ार **2:20 से 3:30** तक — उस शाम वाले समय की जगह जो इस परंपरा की शुरुआत से चला आ रहा था। यह संवत 2083 खोलेगा। इसमें कुछ भी अनुपालन की तारीख़ नहीं है, और यह सामने वाले कॉलम में एक ही वजह से है: इस साल का यही अकेला रविवार है जिस दिन दिया गया ऑर्डर सचमुच लगेगा।

महीने की दो तारीख़ें ज़िम्मेदारी नहीं हैं, मगर अगले महीने का रुख तय करेंगी। **28 अक्तूबर** को **Jio Platforms** की listing है, जिसका ₹30,213 करोड़ का इश्यू रुपये के हिसाब से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा था और भारी oversubscription के साथ बंद हुआ — इतनी बड़ी listing भावना हिलाती है और पखवाड़े भर नक़दी भी। और **16 नवंबर** को **अक्तूबर का WPI** आएगा — पहला सरकारी लागत आँकड़ा जिसमें इस महीने का कच्चा तेल होगा। अगर उस आँकड़े से आपको चौंकना है, तो अभी चौंक लीजिए, जब कुछ करने का वक़्त बचा है।

इस हफ़्ते का सवाल

हर अंक में एक

“बैंक कहता है मेरी ब्याज दर नहीं बदली। मगर loan statement में अब जुलाई से ज़्यादा क़िस्तें दिख रही हैं। क्या वे बिना बताए ऐसा कर सकते हैं?”

दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं, और पैसा दूसरी में है। floating कर्ज़ पर दर बढ़ने पर बैंक के पास दो रास्ते होते हैं: EMI बढ़ा दे, या EMI वही रखकर **अवधि बढ़ा दे**। ज़्यादातर दूसरा चुनते हैं, क्योंकि उसमें बात नहीं करनी पड़ती। आपकी दर “न बदलने” का मतलब आम तौर पर उस दिन की दर है जब आपने पूछा, न कि वह दर जो आपके पिछले **reset** पर लगी — और दोनों benchmark पर ये अलग चीज़ें हैं। तो, क्रम से। एक: sanction letter से पता कीजिए कि आप **EBLR** पर हैं (रेपो से जुड़ा, जो 7 अक्तूबर को 25 आधार अंक हिला) या **MCLR** पर (बैंक की लागत से जुड़ा, जो बॉन्ड बाज़ार के साथ अब भी चल रहा है)। दो: खाते की **rate reset history** लिखकर माँगिए — जनवरी से हर reset पर लगी दर, आज की दर नहीं। बैंकों के पास यह रहती है और ठीक से माँगने पर देते हैं; यही अकेला काग़ज़ है जो बताता है कि असल में हुआ क्या। तीन: पूछिए कि **नई अवधि** क्या है और मंज़ूरी के वक़्त क्या थी। जो कर्ज़ चुपचाप 84 महीने से 97 हो गया, उसने आपसे तेरह क़िस्तों का ब्याज ले लिया और किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी। चार, और यही काम की बात है: आप आम तौर पर बैंक से कह सकते हैं कि अवधि वही रखे और उसके बजाय EMI बढ़ा दे, अगर नक़दी इजाज़त दे। यह अनुरोध है, अधिकार नहीं — मगर बैंक इसे आम तौर पर मान लेते हैं और कर्ज़ की पूरी उम्र में यह कहीं सस्ता पड़ता है।

अपना सवाल भेजिए — हर अंक में एक का जवाब देते हैं

आपको क्या करना है

31 को तारीख़ से आगे नहीं, व्यक्ति से पीछे की ओर चलाइए। TDS statement के लिए payroll चाहिए; Form 3CEB के लिए transfer pricing वाला accountant, जो आम तौर पर आपके auditor से अलग फ़र्म होता है; self-assessment के भुगतान के लिए signatory — और 31 शनिवार है, इसलिए वह पैसा असल में **शुक्रवार 30** को ही चलना चाहिए। फिर **16 नवंबर** को डायरी में पढ़ने की नहीं, फ़ैसले की तारीख़ लिखिए: अक्तूबर का WPI जो भी छापे, आपके दाम तब तक हिल चुके होने चाहिए।

हमने क्या कहा, और हुआ क्या

पिछला अंक, रिकॉर्ड से मिलाकर

सही निकला अंक 10 · बड़ी खबर

> "ऑडिट रिपोर्ट कल देनी है। तीसरी तारीख़ नहीं आएगी।"

21 बिना किसी नए circular के निकल गई। जिसने extension को लंबी राहत की पहली क़िस्त समझा, उसकी filing देर से हुई।

ग़लत निकला अंक 10 · बाज़ार

> "आठ हफ़्ते का घाटे का सिलसिला ख़त्म हो गया" — क़रीब छह महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त।

अगले ही हफ़्ते निफ्टी ने **2.4%** और उसके साथ ज़्यादातर उछाल लौटा दी। ग़लती आँकड़े में नहीं, काल में थी: पखवाड़ा मोड़ नहीं होता — और इसी अख़बार ने आगे चलकर अंक 09 को मोड़ न पकड़ने पर डाँटा। अब हफ़्ते को हफ़्ता ही कहा जाएगा।

सही निकला अंक 10 · GST

> "सिफ़ारिश नियम नहीं होती। अभी इनमें से कुछ भी claim मत कीजिए।"

सत्रह दिन बाद: 9 अक्तूबर को FAQ, 15 को चेयरमैन की अपील, और **एक भी अधिसूचना नहीं**। जिस mismatch व्यवस्था को राहत बताकर छापा गया, वह **अप्रैल 2027** की return अवधि से प्रस्तावित है।

सही निकला अंक 10 · निर्यात

> "हम tariff की दर नहीं छापेंगे: चार बचाव-योग्य आँकड़े चल रहे हैं।"

इस हफ़्ते पाँचवाँ आ गया — Section 122 के तहत सार्वभौमिक 15%, एक स्रोत के हवाले से। दस्तख़त अब भी कहीं नहीं। जिस अख़बार ने अक्तूबर में उन चार में से एक चुन लिया होता, वह नवंबर में सुधार छाप रहा होता।

हर अंक में छपता है। पिछला रिकॉर्ड archive में है। अगर कोई बात इस खाने से छूट गई है जो आपको लगती है कि तुलनी चाहिए, लिख भेजिए — अगले हफ़्ते तुलेगी, उनमें वे भी जो हमारे ख़िलाफ़ जाती हैं।

इकॉनमी एक नज़र में

10 साल की G-sec		7.474%
रेपो रेट		5.50%
ब्रेंट कच्चा तेल		$116.72
रुपया	94.94/$	मज़बूत, जिससे निर्यात की वसूली घटती है
विदेशी मुद्रा भंडार	$721.02 bn	-$5.01 अरब, 16 अक्तूबर तक का हफ़्ता
सिस्टम की नक़दी		₹541.95 cr
WPI / CPI (सितम्बर)		11.39% / 5.54%

Business Standard (यील्ड, नक़दी, भंडार, रुपया), Trading Economics और exchangerates.org.uk (ब्रेंट), MoSPI तथा PIB (CPI, WPI), RBI (नीति)। अक्तूबर में रुपये का रास्ता स्रोतों में एक जैसा नहीं है — एक उसे 9 अक्तूबर को 96.73 बताता है, दूसरा 6 को दिन में 84.43 — इसलिए यह तालिका सिर्फ़ 23 अक्तूबर का तारीख़ वाला बंद भाव रखती है और बाक़ी को बेमेल कह देती है।

इनमें से कोई खबर आप पर लागू होती है ?

बस एक मैसेज कीजिए। हम बता देंगे कि आप पर क्या लागू होता है, कब तक करना है, और किस बात की चिंता नहीं करनी। फिक्स्ड मंथली फीस, कोई लॉक-इन नहीं, नोटिस आया तो वो भी हम देखेंगे — जैसे 1,100+ MSME के साथ पहले से कर रहे हैं।

लोग हमारे पास क्यों आते हैं

- फिक्स्ड मंथली फीस — न छुपा चार्ज, न लॉक-इन
- सब कुछ WhatsApp पर। नोटिस आया तो वो भी हम देखेंगे।
- 7 दिन में books बंद, हर महीने P&L डैशबोर्ड

किसी कारोबारी के काम की है? आगे भेज दीजिए।

The Consulting Crew

theconsultingcrew.in
hello@theconsultingcrew.in
WhatsApp +919251022710
जयपुर · पूरे भारत में

हम क्या करते हैं

GST · इनकम टैक्स · TDS · ROC · पेरोल · CFO सलाह · कंपनी और LLP रजिस्ट्रेशन

अगला अंक

रविवार, 1 नवम्बर 2026

पिछले अंक

हर अंक, मुफ़्त

THECONSULTINGCREW.IN

खबरें कहाँ से

कर्ज़ — यील्ड, नक़दी और दो benchmark — Business Standard — bond yields up ~30 bps in October, and the interest burden, Business Standard — worst bond losing streak in 30 years, Business Today — SBI Research sees the 10-year at 7.6%, Business Standard — RBI's ₹2.5 trillion infusion, and the mixed signal · रुपया, भंडार और तेल की खिड़की — Business Standard — the rupee's recovery against dollar demand and outflows, Bloomberg — the RBI's 10 October measures, including the special oil window, Business Today — whether the measures buy time or need structural follow-up · कच्चा तेल — और सितम्बर के आँकड़े में वह क्यों नहीं है — Trading Economics — Brent at $116.72 on 23 October, exchangerates.org.uk — the 23 October Brent close and the day's range, PIB — provisional WPI for September 2026 (fuel and power at 25.85%) · GST — सिफ़ारिशें, FAQ, और अभी कोई अधिसूचना नहीं — TaxO — CBIC's FAQs of 9 October on the 57th Council's recommendations, TaxGuru — analysis of the 57th Council meeting, NRS Associates — outcomes and the dates attached to them · टैक्स — ऑडिट की तारीख़ टिकी, और 31 अक्तूबर को क्या है — TaxGuru — the extension to 21 October, explained, CAclubindia — audit report 21 October, ITR 21 November, Kunal Darwani — what changed and what did not, including s.92E · व्यापार — tariff का पाँचवाँ आँकड़ा, और दस्तख़त कहीं नहीं — Bloomberg — Trump says the deal is 'pretty close' (20 October), The Arabian Post — the draft is ready, the gaps are not closed, White House — the February framework, 25% to 18% · राजस्थान — direct allotment का रास्ता, आँकड़ों में — Business Standard — 449 applications for 240 plots in phase 12, Business Standard — a fivefold jump in allotments in Q1 FY27, Business Standard — ₹569 crore from 128 investors, and the Udaipur bidding · बाज़ार, दिवाली का सत्र और हफ़्ते का पैसा — Business Standard — NSE and BSE set Muhurat trading for 8 November, Outlook Money — the rare afternoon session, and the Jio issue's records, CNBC — anchor demand for the Jio Platforms IPO, Inc42 — 17 startups, over $184 million, 19–23 October

ज़रूरी सूचना। यह अख़बार The Consulting Crew अपने क्लाइंट और जान-पहचान वालों की जानकारी के लिए निकालता है। यह कोई कानूनी, टैक्स या निवेश की सलाह नहीं है, और इसे पढ़ने से हमारा-आपका क्लाइंट रिश्ता नहीं बनता। आँकड़े, दरें और तारीख़ें छपने के दिन तक की हैं और सरकार के नोटिफिकेशन से बदल सकती हैं। कुछ भी करने से पहले अपने केस के हिसाब से हमसे एक बार पूछ लीजिए। बाज़ार के आँकड़े सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं, कोई शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं।